भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 318
जिसका उत्तर मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

ऑटो की बिक्री में कमी

318. **श्री के नवासखनी :**
श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2019 में लगातार 11वें महीने में भारत में ऑटो की बिक्री में गिरावट आई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ऑटोमोबाइल की बिक्री में गिरावट के कारण क्या है जिसके परिणामस्वरूप ऑटो सेक्टर में नौकरियों का नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा ऑटो बिक्री में इतनी गिरावट पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) पिछले कुछ महीनों से ऑटोमोटिव सेक्टर सहित सभी क्षेत्रों में आवर्ती मंदी है। लेकिन त्यौहारी माँग से यात्री वाहन सेगमेंट में वर्ष-दर-वर्ष 0.3% की दर से वृद्धि हुई है।

(ख) ऑटोमोबाइल की बिक्री में गिरावट के लिए अनुभव-संबंधी कारणों के साथ-साथ अनेक वित्तीय और विनियामक कारण हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- ऑटो सेक्टर के लिए वित्तीय उपलब्धता में कटौती
- वाणिज्यिक वाहनों के लिए 25% तक एक्सल भार सीमा में बढ़ोतरी, बढ़ी हुई माल-भाड़ा क्षमता, जिससे नए वाहन की मांग में कमी आई
- 3 वर्षों (नई कारों) और 5 वर्षों (नए दुपहियों) के लिए दीर्घावधिक तीसरा पक्ष बीमा प्रिमियम के अग्रिम संग्रहण के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण वाहन की लागत में बढ़ोतरी
- डीलरों के लिए 25% से 60% तक कोलैटरल में बढ़ोतरी, जिसके परिणामस्वरूप डीलरों के इन्वेन्ट्री वित्त में कटौती हुई
- बीएस III से बीएस IV में परिवर्तन की तरह बीएस VI मानकों के साथ स्टॉक को क्लीयर करने के लिए ओईएम द्वारा छूट से पहले ही खरीद का स्थागन

(ग) जब कभी आवश्यक होता है, सरकार एक नीति निर्माता के रूप में हमेशा ऑटो सेक्टर के व्यापक और सतत विकास के लिए अनेक उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने एवं इसमें सुधार करने का प्रयास करती है। ऑटोमोटिव में मंदी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

- कारपोरेट कर को 22% तक कम करना
- भविष्य में आईसीई और ईवी का पंजीकरण जारी रखना
- स्क्रैपेज नीति पर विचार किया जा रहा है
- नई कारों के पंजीकरण में प्रस्तावित वृद्धि को जून, 2020 तक आस्थगित कर दिया गया
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ₹70,000 करोड़ की निधि जारी की गई
- खरीदे गए वाहन पर लिए जाने वाले ब्याज को रेपो रेट से जोड़ना

*****